(f) the measures taken to correct the adverse terms/conditionalities betwen rural and urban people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) An outlay of Rs. 30,000 crores has been provided for Rural Development in India during the Eighth Plan period.

(b) The percentage of funds earmarked for establishment expenses, salaries etc. differs from scheme to scheme. However, the percentage of funds ear-marked for the said purpose is very small and the major portion of the funds are meant for implementation of the Rural Development schemes.

(c) The implementation of various schemes for Rural Development rest with the State Governments and no pilferage has been reported by them.

(d) and (e) No, Sir. However, the concept of Aggregate Measurement of Support (AMS) used in the Uruguay Round Agreement on Agriculture is a negotiated concept designed to measure the trade distorting domestic support given to agriculture by member countries of GATT. It does not take into account a large variety of support measures for the agriculture sector. For this reason it is not appropriate to equate the concepts of AMS and subsides or to conclude that a negative figure of AMS is the same thing as a negative subsidy.

(f) Various schemes for Rural Development are being implemented in rural areas only which help in checking migration from rural areas to the urban areas in addition to the stated objectives of these programmes.

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति

1474. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु उसके कार्यान्वयन में परिवर्तन करने संबधी उपाय सुझा दिये हैं

(ख) यदि हां, तो ये सुझाव क्या-क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों को लागू करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि [illegible] तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (: उत्तमभाई पटेल) : (क) जी हां। समिति ने हाल ही में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को दे दी है।

(ख) समिति द्वारा दिए गए कुछ मुख्य सुझाव ये हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिकाधिक भागीदारी।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों का चयन परिसम्पत्तियों के संचालन और रखरखाव में कुशलता, अभिरुचि और अनुभव रखने वालों में किया जाना चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य लोगों को भी सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि उन्होंने ट्राइसेम अथवा अन्य

संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो अथवा वे अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर लें।

(3) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार काम को जमाने से पूर्व सहायता देने के बाय काम जम जाने के बाद सहायता दे की पद्धति अपनाना।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋणों को बेहतर वसूली के उपाय।

(5) कार्यशील पूंजी की पूर्ति करने की आवश्यकता।

(6) ऋण चुकाने की व्यावहारिक अनुसूची तैयार करना और प्रतिभूति मुक्त ऋणों की सीमा बढ़ाना।

(7) बेहतर योजनायें बनाने और संरचना संबंधी विकास करने को तरजीह देना।

(8) अधिक ऋण और अधिक सबसिडी मुहैया कराकर प्रति परिवार सहायता के स्तर में वृद्धि करना।

(ग) और (घ) इस रिपोर्ट को इस समय भारतीय रिजर्व बैंक और ग्रामीण विकास मंत्रालय में जांच की जा रही है। मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से रिपोर्ट के संबंध में अंतिम निर्णय लेगा।

Rural Financial Institutions

1475. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that to reduce financial poverty, Government have created a network of Rural Financial Institutions (RFIs), if so, the details thereof;

(b) whether it is a fact that though the number of banks may have grown, the village money lender is still virtually the only source of credit;

(c) whether it is a fact that Government have not been able to replicate the success of other countries in creating RFIs to make them either self-sustaining or actually competent in meeting the needs of the rural poor if so, the reasons therefor; and

(d) the details of steps benig taken by Government to improve the service of these banks to attain the goals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) Under the multi-agency approach to rural lending in the country there is a network of cooperatives, rural branches of commercial banks and regional rural banks which cater to the credit needs of rural areas. Details are as under:

	No. of Institution 2nd June 1993
8	
Co-operatives.	
State Co-operatives Banks	28
Central Co-operative Banks	354
Primary Agricultural Credit Societies	8834
fltate Land Development Banks	20
Primary Land Development Banks	706